## अध्यक्ष, राज्य फॉर्मर्स कमिशन, पंजाब

हमें सभी सदस्यों को यह सूचना देते हुए खुशी हो रही है कि श्री अजय वीर जाखड़, अध्यक्ष, भारत कृ-ाक समाज ने पंजाब राज्य के राज्य फॉर्मर्स कमिशन के अध्यक्ष का पद-भार ग्रहण किया है।

संपादकीय

यह किसानों के लिऐ नहीं

उर्वरक आर्थिक सहायता के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का वास्तविक लाभ उद्योग को होगा।

उर्वरक आर्थिक सहायता के संबंध में उद्योग रणनिति वैसी ही रहेगी जैसी तंबाकू उद्योग की प्रतिक्रिया करने पर व-र्ा 1954 से कैंसर होने के दावे किऐ गऐ थे। स्टैनफोर्ड के एक इतिहासकार रॉबर्ट प्रॉक्टर ने एक ृाब्द खोजा 'संशयवादिता' अर्थात जब जानबूझकर अज्ञानता दिखाई जाऐ और विवाद रहित तथ्यों से बहस का समाधान न निकले।

उर्वरक आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, योजना के प्रसतावकों का दावा है कि ऐसा करने से किसानों के बिक्री बिंदु से लेकर और माल के लिक होने से बचा जाऐगा और उद्योग को भी समय पर भुगतान होगा, यह देखने में अच्छा है लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। ऐसे छोटे मोटे लाभ प्राप्त करने के लिऐ बड़ा जौखिम उठाने की आवश्यकता नहीं होती। किंतु वास्तव में ऐसा ही हो रहा है।

वास्तविकता यह है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उद्देश्य उर्वरक उद्योग को लाभ पहुंचाना है। 17 जिलों में यह बडी योजना को लागू करना एक साहसिक कदम है। किंतु यह गुमराह करने वाला तथ्य है कि इस योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिऐ कठोर कदम नहीं उठाऐ जाते। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का अंतिम रूप केवल उर्वरक उद्योग पर निर्भर होगा और इसकी कीमत भी वह निर्धारित करेगा तथा सरकार से सहायता लेने का बोझ किसानों को उठाना होगा। यह व-र्ा 1960 में अमेरिका के चीनी उद्योग के समान है जिसमें वैज्ञानिकों और विद्वानों को अच्छा लाभ देकर उनसे चीनी

और हृदय बिमारियों को अलग रखने का कार्य सौंपा गया था। पर्याप्त अवसर को देखते हुऐ पहली बार अंतर्रा-ट्रीय उर्वरक की बडी-बडी कंपनियां जैसे यारा ईंटरनैश्नल ने भारतीय यूरिया उर्वरक के संयंत्रों को खरीदना ुरू कर दिया है, ताकि अधिकतम लाभ अर्जित कर सकें।

उर्वरक मूल्य के 2 घटक हैं - थोक मूल्य जो फिक्स होता है और उर्वरक घटक जो भिन्न-भिन्न होता है। आज चाहे अंतर्रा-ट्रीय यूरिया के मूल्य में उतार चढाव कितना भी हो लेकिन किसानों को रू. 284 में यूरिया का बैग मिल जाता है। लेकिन नई योजना लागू होने से इसका उल्टा हो जाऐगा। यूरिया की बोरी का मूल्य अलग-अलग हो जाऐगा, लेकिन आर्थिक सहायता स्थाई रहेगी। व-र्ा 2008 में अंतर्रा-ट्रीय यूरिया के मूल्य 500 डॉलर प्रति टन तक पहुंचे। लेकिन भारत में यूरिया की बोरी का मूल्य रू. 239 प्रति बोरी था। अंतर्रा-ट्रीय मूल्य आज के यूरिया मूल्य से आधे हैं। यदि यूरिया के मूल्य अंतर्रा-ट्रीय बाजार में व-र्ा 2008 के स्तर तक पहुंच जाऐं, तो नई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना से किसानों को एक बोरी के लिऐ रू. 1,200 तक की कीमत चुकानी पड सकती है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अंतिम रूप से स्प-ट करने के लिऐ एक सही ओर समान उदाहरण है कि जैसे ऐल.पी.जी. गैस सिलेंडर की कीमत उपभोगता को चुकानी पडती है, वैसे ही उर्वरक की कीमत किसानों को चुकानी पडेगी। पहले ऐल.पी.जी. पर उपभोगता को 1 सिलैंडर के लिऐ केवल रू. 450 देने पडते थे, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू होने के बाद इसकी कीमत रू. 805 तक पहुंच चुकी है। उपभोगता पूरी कीमत देकर सिलैंडर खरीदता है और बाद में इसकी सबसीडी का दावा करता है। इसी प्रकार किसानों को अब उसी कीमत पर यूरिया की बोरी पर सबसीडी मिलती थी। अब नई योजना लागू होने से किसानों को अपनी भूमि के दस्तावेजों के साथ पहले रजिस्टर कराना होगा और उसी समय बोरी की पूरी कीमत देनी होगी और बाद में वे सबसीडी का दावा करेंगे। इस प्रकार किसानों के लिऐ पूंजी व्यय और उधार लेने की आवश्यकता एक तिहाई बड जाऐगी। सभी जानते हैं कि किसानों द्वारा आत्महत्याऐं करने का आमतौर पर कारण ऋण ही होता है।

जैसा टिम हारफोर्ड ने स्प-ट किया है अपनी पुस्तक 'द प्रॉब्लम विद फैक्ट्स' में 'मिथ्या, विवाद, घबराहट' ; इस योजना में पहले उर्वरक उद्योग को ामिल करने की सोची, इसके बाद उर्वरक उद्योग के लाभ के स्थान पर किसानों को प्राथमिकता दी

और तीसरे चरण में किसानों की चिंता और वास्तवीक स्थिती को नजरअंदाज करके उर्वरक उद्योग के पास मौजूद उनके कहे पर चलने वाले विशे-ाज्ञों का परामर्श मानने के बारे में सोचा गया।

नई योजना के अंतर्गत किसान उर्वरक की खरीद सबसीडी मूल्य पर करने की मात्रा सीमित होगी। गेहूं, चावल, आलू, दालें, बाजरा आदि के लिऐ भिन्न प्रकार के पौि-टक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो भूमि और फसल के चयन पर निर्भर करता है। नीति में इस तथ्य को नहीं माना गया और भारतीय कृि-ा की पूरानी नौकरशाही, तानाशाही पर ही विश्वास किया गया जिनके परामर्श कई बार असफल हो चुके हैं। आज 10 करोड किराऐ की खेती करने वाले किसान सबसीडी पर उर्वरक खरीद सकते हैं लेकिन नई योजना में वे सबसिडी पर उर्वरक नहीं ले पाऐंगे, क्योंकि भूमि उनके नाम पर नहीं है। उर्वरक आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लाभकारी हो सकता है यदि किसानों के हित की सखती से रक्षा की जाऐ। किसान संसद से अपने हितों की रक्षा की गारंटी चाहते हैं, क्योंकि मुह से बोलने पर कोई कानून लागू नहीं होता। किसान आहत हैं और ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की उर्वरक संबंधी सहकारी संस्थाऐं किसानों की प्राथमिक चिंता अर्थात जीवनयापन पर कोई ध्यान नहीं देती। अभी तक सरकार की ओर से कुछ सहायता मिल जाती थी लेकिन अब अंतर्रा-ट्रीय उर्वरक माफिया के विरूद्ध आखरी कवच भी समाप्त होता नजर आ रहा है।

एक 'नऐ भारत' के व्यापक दृि-टकोण के बारे में सरकार में ही आर्थिक नीतियों के स्तर पर कई मतभेद हैं। सरकारी अधिकारी का मतलब केवल उर्वरक सबसीडी व्यय पर अधिपत्य स्थापित करना है। सरकार को सलाह देने वाले कई अर्थशास्त्री एक विडंबना बिंदु तक पहुंच चुके हैं और दुख के साथ यह कहना पडता है कि किसानों की आय दोगुनी करने का नारा एक मजाक बनकर रह गया है। किसानों का दर्द उर्वरक उद्योग द्वारा किऐ जा रहे प्रचार और ाोरगुल में दब रहा है। क्या कोई किसानों का दर्द सुन रहा है ?

# नोटबंदी की समस्याऐं एवम् बाधाओं को दूर करना
# कृ-ि उत्पाद, मुर्गी पालन और वृक्षारोपण

सुबीर दास

8 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री ने एक अनिवार्य आदेश जारी किया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी रू. 500 और रू. 1,000 के नोट तत्काल प्रभाव से नहीं चलेंगे, अर्थात् कुल कीमत में बाजार में नकदी का 86 प्रतिशत लोगों के हाथों से अदृश्य अथवा व्यर्थ हो गया। इसे लागू करने के कारण जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या इस पर सर्वसम्मती थी या नहीं बल्कि इसके परिणामों को जानना महत्वपूर्ण है।

कृ-ि क्षेत्र पर इसके दु-प्रभाव की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कृ-ि क्षेत्र में अधिकांश कार्य नकदी में किऐ जाते हैं और वह भी ऐसी स्थिति में जब सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में इतने नऐ नोट नहीं थे की वे पुराने नोटों को बदल पाते। वास्तव में आरंभ के 45 दिन तक तो भारतीय रिर्जव बैंक ने रू. 2,000 के नऐ नोट बांटे जिन्हें भुनाना न तो सरल था और न ही कोई ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत इन्हें छोटे नोटों में बदला जा सकता था।

इसमें कोई संदेह नहीं की कृ-ि क्षेत्र पर इसका घातक प्रभाव पडा - देशभर के सभी लोगों को यह पता था और उन्होंने महसूस भी किया कि किसानों की किस्मत पर फिर आक्रमण हुआ है और इसके कई सबूत भी सामने आऐ। व-र् 2014-15 में कृ-ि वृद्धि दर केवल 0.2 प्रतिशत थी और व-र् 2015-16 में भी लगातार सूखा पडने के कारण 1.2 प्रतिशत रही थी। इस सूखे के कारण किसानों पर प्रचंड मार पडी।

इस व-र् (अक्टूबर, 2016) तक कृ-ि वृद्धि दर 4 प्रतिशत होने की संभावना थी, किंतु नोटबंदी ने सबकुछ उल्टा कर दिया। आर्थिक सर्वेक्षण में भी यह माना गया कि देश में किसी भी आर्थिक कार्य या कारोबार के लिऐ नकदी न होने से विपरीत प्रभाव पडेगा, जैसे की कृ-ि उत्पादकों को अपने मजदूरों की मजदूरी देने के लिऐ नकदी की आवश्यकता होती है। हालांकि इसका अत्यधिक नुकसान होने से बच गया।

नोटबंदी का आदेश ृीतकाल बिजाई के समय के मध्य में आने से किसानों पर बुरा प्रभाव यह पडा कि बीजों की खरीद के लिऐ उनके पास पैसा नहीं बचा। ग्रामीण भारत के लिऐ यह सदमा सहना असंभव हो जाता यदि कस्बों और नगरों जैसा जुगाड वहां उपयोग में नहीं लाया जाता। यह घो-णा ऐसे समय में की गई जब किसान रबी की फसल और ृीतकालिन सब्जियां उगा रहे थे या उगाने की तैयारी कर रहे थे। सरकार का दावा है कि रबी की फसल में यूरिया की मात्रा का उपयोग बढना (13 जनवरी 2017 के दिन पिछले व-र् की तुलना में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि) सिद्ध करता है कि नोटबंदी का ुन्य प्रभाव पडा, लेकिन सरकार जमीनी हकीकत से अंजान रही।

नीति आयोग के डॉद्म रमेश चन्द और श्री जसपाल सिंह सदस्य एवम् परामर्शी ने उस स्थिति के आधार पर यह नि-ाकर्श निकाला कि '30 दिसंबर तक रबी की बुआई का कार्य 88 प्रतिशत क्षेत्र में पूरा हो जाता है। इस व-र् 91 प्रतिशत क्षेत्र से अधिक भाग पर बुआई की जा चुकी थी', वे इस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि रबी क्षेत्र में वृद्धि का कारण अच्छा मॉनसून होने से खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 9 प्रतिशत अधिक था। ृीतकालिन फसल भी अच्छी होने की संभावना थी।

लाईव मिंट (जनवरी 30, 2017) का कहना है कि 'व-र् 2016-17 में सामान्य मॉनसून होने के कारण रा-ट्रीय आय जनवरी तक विशे-ाकर कृ-ि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत तक जाने का अनुमान था - इसका आधार खरीफ खाद्यान्न 9 प्रतिशत अधिक होना और ृीतकालिन फसल उत्पादन का लक्ष्य भी आशाजनक था।' आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछले व-र् में उगाई गई रबी की गेहूं और दालों (चना) की फसल का क्षेत्र अधिक था और इस कारण से इनका उत्पादन बढने की संभावना है लेकिन इसके लिऐ किसानों को बीज, उर्वरक, ऋण और मजदूर मिल जाने चाहिऐ, किंतु इन सब में नोटबंदी के कारण बाधाऐं उत्पन्न हुईं।

व-र्ा 2014–15 और 2015–16 की तुलना में 21 दिसंबर, 2016 तक की अवधि में रबी की फसल के लिऐ उर्वरक की खरीद में 7.47 और 7 प्रतिशत की क्रमशः कमी आई। जितने क्षेत्र में फसल उगाई गई थी, यह उस दावे का उल्टा सिद्ध हुआ। उर्वरक के कम उपयोग से फसल का उत्पादन भी कम ही होगा। इन सब तथ्यों में ध्यान में रखते हुऐ सरकारी अनुमानों के दावों की सत्यता पर बड़ा संदेह है।

बागवानी और मछलीपालन कृ-ि क्षेत्र के अभिन्न भाग हैं जो अपनी कहानी सव्यम् ब्यान कर रहे हैं। अभी अंतिम आंकडे तो उपलब्ध नहीं हैं लेकिन नोटबंदी के दु-प्रभाव स्प-ट नजर आ रहे हैं। 7 नवंबर नवी मुम्बई के वाशी में नियमित थोक फल मंडी में लगभग 250 ट्रक आऐ थे, जिसमें प्रत्येक ट्रक में 10 टन तक कृ-ि उत्पाद था। अगले दिन भी कृ-ि उत्पाद विपणन समिति द्वारा संचालित मॉक्रेट में इतनी ही संख्या में ट्रक आऐ थे लेकिन इसके अगले दिन इनकी संख्या कम होकर 170 ट्रक रह गई। एक ही रात में फलों की आपूर्ति में लगभग 30 प्रतिशत की कमी आई।

अभी तक कोई ऐसे आंकडे प्राप्त नहीं हुऐ जिनमें व-र्ा 2016–17 में बागवानी क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र अथवा उत्पादन का अनुमान लगाया जा सके। लेकिन यह सत्यता है कि व-र्ा 2013 से खाद्यान्न की तुलना में वागवानी का उत्पादन अधिक बढ़ता रहा है। खरीफ और रबी फसल मौसम में की जाने वाली बिजाई की साप्ताहिक प्रगति का अनुमान केवल सुनी–सुनाई और राज्यों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर आधारित है न की वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण अथवा सैटेलाईट से प्राप्त फोटो के आधार पर।

इसी बीच में मुर्गीपालन उद्योग रू. 1,500 करोड़ की हानि होने की शिकायत की है। रू. 95,000 करोड़ के इस उद्योग में लगे हुऐ लगभग 2.5 करोड़ लोग 25 करोड़ अंडों की बिक्री नहीं कर सके, जिनकी बिक्री अक्टुबर – दिसंबर की अवधि में होनी थी। वी. ह-र्वर्धन रेड्डी, तेलंगाना मुर्गीपालन प्रजनक संघ के उपाध्यक्ष ने भी एक गंभीर शिकायत की है। उनका कहना है कि नवंबर से फरवरी से समय में तयौहारों के कारण मुर्गीपालन उद्योग का अच्छी मांग का मौसम होता है। इस मौसम में नोटबंदी के कारण घातक मार पड़ी। अपनी हानियों को कम करने के लिऐ हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इन पक्षियों को मार दें, किंतु फिर भी हमारे निवेश और मानव क्षमता पर बुरा असर पडेगा ही। (नोटबंदी का प्रभाव : हैदराबाद के प्रसिद्ध चिकन बिरयानी उद्योग को हानि, राज्य में मुर्गीपालक संकट में हैं।)

कृ-ि पर निर्भर सभी उद्योगों में रोजगार बुरी तरह से प्रभावित हुआ। समाचार पत्रों में बहुत से समाचार छपे की नोटबंदी के कारण व्यस्त बुआई के सीजन में कृ-ि मजदूरों को नकद में भुगतान न करने से कई मजदूर अपने दूर-दराज के गांव में लौट गऐ। 14 नवंबर, 2016 को सरकारी निर्णय की ग्रामीण सहाकरी बैंक पुराने नोट न जमा करेंगे और न ही बदलेंगे, इससे किसानों और खेतों के मालिकों को बुआई और फसल उगाने के उचित समय होने के कारण बड़ी हानि झेलनी पडी, क्योंकि पैसा निकालने की भी सीमा थी।

श्रम मंत्रालय के आंकडे भी इसी प्रकार की सूचना दे रहे हैं, कि रबी मौसम में फसलों की बुआई पर अच्छा प्रभाव नहीं पडेगा। यह दर्शाता है कि ृीतकालिन फसलों की अधिक क्षेत्र में बीजाई करने के बाद भी ग्रामीण मजदूरी में कमी आ रही थी। दिसंबर, 2016 (शीतकालिन बीजाई का व्यस्त समय) में भी न्यूनतम मजदूरी के दिनों की संख्या में सामान्य वेतन की ही खबरें मिली। जिसमें व-र् दर व-र् रू. 292 प्रति दिन का वेतन मिलता था, यह वेतन भी मिलना कठिन हो गया, यह आंकडे श्रम मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2017 में जारी किऐ गऐ थे। यह दिसंबर 2015 में सूखा प्रभावित समय से 3.9 प्रतिशत वृद्धि दर से अधिक थे, लेकिन दिसंबर, 2014 में 6.6 प्रतिशत दर की वृद्धि दर से काफी कम थे, लेकिन व-र् 2013 में 26 प्रतिशत और 2012 के 18 प्रतिशत से बहुत निचे थे।

वर्ष 2016-17 में चावल, गेहूं और दालों का रिकॉर्ड उत्पादन और कृ-ि कार्यों में वृद्धि होने पर भी न्यूनतम मजदूरी कम रही। इसका कारण नोटबंदी था।

देश भर से सूचनाऐं मिली की नवंबर और दिसंबर 2016 में अथवा नोटबंदी की घो-णा से पहले किसान अपनी फसलों की बिक्री सस्ते में ही कर रहे थे। रमेश चंद और जसवंत सिंह का कहना है कि नवंबर में धान, सोयाबीन और मक्का जैसी मुख्य फसलों के मूल्यों पर नोटबंदी का कोई प्रभाव नहीं पडा और देश की कृ-ि उत्पाद मंडियों में इनके थोक मूल्य अक्टूबर महीने की तुलना में नवंबर में लगभग 3 प्रतिशत अधिक थे।

उन्होंने इतना तो माना कि दिसंबर 2016 में मक्का और सोयाबीन के मूल्य कुछ कम हुऐ लेकिन यह जोड़ दिया कि पिछले 2 महीने पिछले व-र् की तुलना में धान के मूल्य बढ़े। कई अन्य फसलों के भाव भी दिसंबर में गिरे। बहुत से राज्यों में धान पर

समर्थन मूल्य उपलब्ध है, लेकिन अन्य फसलों के मूल्य मांग और आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करते हैं।

नोटबंदी से खरीददारी की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। इस कारण किसानों द्वारा उगाई गई बढ़ी मात्रा में सब्जियां और अन्य बागवानी फसलें भी प्रभावित हुई। इस प्रकार किसानों को दोहरी मार पडी, एक तरफ तो उनका बडा हुआ उत्पादन नहीं बिक रहा था, क्योंकि खरीददारों के पास पैसा नहीं था, और दूसरी तरफ वे तंगी से जूझ रहे थे।

हम इस बात को आसानी से नहीं भूल सकते कि टैलीविजन और अखबारों में यह दिखाया गया है कि किसान अपनी सब्जियों और फलों को निराश होकर कैसे सडकों पर फेंक रहे हैं। अधिक आपूर्ति होने से भावों में कम आनी चाहिऐ थी लेकिन इसके विपरित कीमतें बहुत ज्यादा गिर गई क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी के कारण खरीद क्षमता नहीं रही थी। आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जनवरी, 2017 को समाप्त महीने में खाद्य मुद्रास्फीति के आंकडों से यह तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। व-र्ा दर व-र्ा के आधार को देखते हुऐ थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई।

उत्तरी भारत में चाय बागान क्षेत्र को नोटबंदी ने कैसे हानि पहुंचाई ? उत्तर भारत में इस बार बडे पैमाने पर चाय उत्पादन हुआ था। संयोगवश इसका मौसम तब समाप्ति पर था जब नोटबंदी की घो-णा की गई, इस कारण इस उद्योग पर कम प्रभाव पडा। लेकिन मांग को देखते हुऐ यह स्प-ट था कि खरीददार के पास पैसा न होने के कारण उन्होंने अपने उपयोग मात्र के लिऐ ही सामान्य खरीद की। घरों के सामान की कटौती की गई और इस कारण मांग में कमी आई। मांग में कमी के कारण चाय के मूल्यों में भी कमी देखी गई।

आशा है कि आने वाले महीनों में इस कमी को पूरा कर लिया जाऐगा, लेकिन तब तक चाय क्षेत्र में लगे मजदूर नोटबंदी से प्रभावित हो चुके होंगे। बागान में मजदूरों को प्रत्येक सप्ताह या 15 दिन में नकद भुगतान किया जाता है। राशि निकालने की सीमा होने के कारण इन्हें मजदूरी देना कठिन हो गया। कुछ स्थानों पर तो मजदूरों को एक महीने तक भुगतान नहीं किया जा सका। चाय उत्पादक राज्यों में अंत में

राज्य प्रशासन ने अपने राज्य के राजस्व से नकद राशि निकालकर उनकी सहायता की, चाय कंपनियों ने इसके बदले में राज्य सरकारों के राजस्व में पैसा जमा कराया।

इससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि मजदूर नकद भुगतान चाहते थे, इसका कारण उन्हें दूर-दूर बैंक की ाखाओं और ऐ.टी.एम. से पैसा लेने जाना पडता था, जिसके लिऐ उन्हें लंबा सफर तय करना पडता था। चाय उद्योग प्रयास कर रहा है कि बैंक मजदूरों के मकानों के आस-पास नकद राशि निकालने की सुविधा प्रदान कर दें। एक अन्य पहलू है कि नोटबंदी से स्थानीय हाट और बाजार भी नहीं बचे। आमतौर पर मजदूरी मिलने वाले दिन चाय बागानों के आस-पास एक लोकल बाजार आ जाता है। इससे चाय बागान के मजदूर अपनी रोज उपयोग में आने वाली आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर लेते हैं। पिछले 3 महीनों में इन पर भी बुरा असर पडा है और अभी भी इनकी बिक्री में कमी जारी है। इस प्रकार से कई लोग जो अपना गुजारा लोकल बाजार में वस्तुऐं बेचकर करते थे, उन्हें बडी हानि उठानी पड रही है।

एक ऐसे व-र् में जब पूरे भारत में आमतौर पर मॉनसून अच्छा होने की संभावना थी, तो किसान यह आशा कर रहे थे की उनकी आय में जबरदस्त वृद्धि होगी, लेकिन किसानों की आशाओं पर पानी फिर गया। बहुत से क्षेत्र जैसे विदर्भा में पिछले कई सालों से विशे-कर 2015-16 तक अच्छा मॉनसून नहीं था। उन्हें यह आशा थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार अच्छी फसल से उन्हें लाभ मिलेगा और वे सारी हानि की पूर्ति कर लेंगे, लेकिन नोटबंदी के कारण उनकी आशाओं पर विराम लग गया।

यद्यपि व-र् के पहले 6 महीने में कृ-ि क्षेत्र का परिणाम अच्छा होगा लेकिन अगले 6 महीने में विचारणीय कमी देखने को मिलेगी। सरकार नोटबंदी के काल्पनिक लाभों का बखान करते हुए नहीं थक रही, किंतु सरकार के अपने आर्थिक सर्वेक्षण कुछ और कहानी ब्यान करते हैं कि नोटबंदी के कारण कई क्षेत्रों पर विपरित प्रभाव पडा है, जैसे की नौकरी गंवाने, कृ-ि आय में कमी और सामाजिक असंतो-ा की रिपोर्ट मिली है, विशे-कर देश की अर्थव्यवस्था के गैर-संगठित क्षेत्र और नकदी गहन उद्योगों पर विपरित प्रभाव पडा है, किंतु एक व्यवस्थित विशले-ाण नहीं किया जा सकता, इसका कारण व्यापक आर्थिक आंकडे उपलब्ध नहीं होना है।

लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में यह माना गया है कि नकद राशि वाले क्षेत्रों (कृ-ि, रियल एस्टेट, आभू-ाण) पर बुरा प्रभाव पडा। 'नौकरी गंवाने, कृ-ि आय में कमी और सामाजिक असंतो-ा जैसे नकद राशि पर निर्भर क्षेत्रों' पर वार्ता होती रहेगी।

चार्टर्ड अकाउटेंट, बरूआ ऐण्ड ऐसोसिऐटस ग्रुप के पूर्व सी.ई.ओ. एवम् ऐन्ड्रयू यूले ऐण्ड कम्पनी लिमिटेड के पूर्व निदेशक।